National Journal of Multidisciplinary Research and Development
ISSN: 2455-9040
Impact Factor: RJIF 5.22
www.nationaljournals.com
Volume 3; Issue 1; January 2018; Page No. 844-848

भारत सार्क तथा अन्य क्षेत्रीय संगठनों के साथ बढ़ते कदम

अनिल कुमार यादव
शोध छात्र, राजनीति विज्ञान विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, भारत।

प्रस्तावना

किसी क्षेत्रीय संगठन का हिस्सा बनने के बाद हर देश के लिए 'क्षेत्रीयता' का अर्थ और उद्धदेश्य बदल जाता है। भौगोलिक सामीप्य किसी भी क्षेत्रीय ब्लाक के गठन की आधारशिला होती है। क्षेत्रीय एकजुटता और सहयोग के लिए एक दूसरे का हाथ थामने वाले देशों के लिए यही भौगोलिक सामीप्य प्राकृतिक उत्प्रेरक का काम करता है। तार्किक उपसिद्धांत के मुताबिक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक गठबंधन देशों की सीमा के पार लोगों को करीब लाता है जिससे आर्थिक–सामाजिक मुद्दों में सहयोग को प्रोत्साहन और देशों के बीच आपसी विश्वास पैदा होने की उम्मीद की जाती है। देश गहरे आर्थिक एकीकरण की दिशा में आगे बढ़ते हैं और तब उनके बीच अपनी क्षेत्रीय संरचना के लिए चिंता का बोध विकसित होने में मदद मिलती है। जैसे यूरोपीय यूनियन (ईयू) यूरोपियनों के लिए ऐसोसिएशन ऑफ साउथइस्ट एशियन नेशंस (अशियान) दक्षिणपूर्व एशियाई के लिए अफ्रीकन यूनियन (एयू) अफ्रीकी देशों के लिए हैं, उसी तरह साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन (सार्क) दक्षिण एशियाई देशों के लिए है। देशों में अंतर्निहित आर्थिक, राजनीतिक और भूराजनीतिक प्राकृतिक विविधताओं को देखते हुए हालांकि दक्षिण एशियाई सहयोग या फिर ऐसे किसी अन्य क्षेत्रीय निकाय के लिए एक रोल मॉडल तय करना मूर्खतापूर्ण तकनीकी रुप से अस्वीकार्य होगा। हालांकि सार्क और असियान में कई समानताएं हैं जिनका सार्क अपने क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने में लाभकारी तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। इस दिशा में आजमाए जाने वाले ऐसे किसी तरीके का असर उसके राजनीतिक नेतृत्व की मंजूरी का निर्भर करेगा।

क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशिया की अंतः शक्ति

हाल के वर्षों में उत्पन्न राजनीतिक परिस्थितियों के आलोक में उभरें संदेह से उत्तर–दक्षिण एशियाई देशों के रीति–रिवाज में कतिपय समानता के कारण इसके सदस्य देश सांस्कृतिक, नस्लीय और धार्मिक के लिहाज से एक दूसरे के करीब है। दक्षिण एशिया क्षेत्र की विपुल और विविधताओं से भरी संभावना उसके जमीनी स्वरुप, जलवायु क्षेत्रों, वन स्रोतों की विविधता और वृहद स्तर पर जल विद्युत उत्पादन की संभावनाओं को समेटे नदियों के विस्तृत जाल के साथ–साथ प्रचुर खनिज संपदा में दिखाई देता है। भौगोलिक समीपता, सांस्कृतिक एकरुपता और साझी ऐतिहासिक विरासत भी क्षेत्रीय आर्थिक एकजुटता बनाने के लिए अत्यंत उपयोगी है। वस्त्र, कपास, अन्न, परिधान, गन्ना, प्लास्टिक और रसायनिक पदार्थ जैसे क्षेत्रों में व्यापार किया जा सकता है। भूमंडलीकरण ने जो चुनौतियॉ और अवसर पैदा किए हैं उनसे दक्षिण एशिया के लोगों के विभिन्न प्रतिद्वंदी समुदायों के बीच बाध्यता पैदा हुई है। इससे लोगों के बीच दक्षिण एशियाई पहचान की भावना को बढ़ावा देने वाले तत्वों पर पर्याप्त जोर देने के कारण ही यूरोप और दक्षिण एशिया दोनों में एक जैसी परिस्थिति निर्मित हुई है। भूटान का राजधानी थिंपू में 28–29 अप्रैल 2010 को आयोजित 16वें सार्क शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने खुले तौर पर अपने भाषण में प्रसांगिकता के साथ 'दक्षिण एशिया में अपने–अपने देशों और संपूर्ण दक्षिण एशिया क्षेत्र में सम्मिलित विकास का नजरिया (जी न्यूज 2010) पेश किया था।

सार्क : क्षेत्रीय सहयोग का परिपेक्ष्य

बड़े पैमाने पर प्रत्यक्ष और परोक्ष बाध्यताओं को देखते हुए दक्षिण एशिया में देशों की सीमा के आरपार लोगों को जोड़ने वाले ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध से अपरिमित लाभ लेने के लिए क्षेत्रीय सहयोग को एक जरिया के रुप में देखा जा रहा है, जागरुक, समग्र और विस्तृत नजरिए का अभाव और सार्क के सदस्य देशों के बीच मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी की वजह से यह उपाय लंबे समय एक ठंडे बस्ते में पड़ा रहा। जिस समय चमत्कारिक आर्थिक प्रगति के लिए क्षेत्रीय एकजुटता को एक मंत्र माना गया था। उसी दौरान इसका गठन किया गया था। सार्क शुद्धरुप से एक आर्थिक समूह है और इसे अंतर्देशीय साझेदारी मंच की बजाय राष्ट्रीय समृद्धि और स्थायित्व बढ़ाने का माध्यम माना गया। 1985 में सार्क के पहले शिखर सम्मेलन के उद्घाटन में ही यह ध्वनित हुआ था। उस समय तत्कालीन नेपाल नरेश बीरेंद्र बीर विक्रम शाहदेव ने कहा था, 'सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और आर्थिक जैसे क्षेत्रों में प्रयासों और आपसी बातचीत के जरिए शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का स्थायी वातावरण तैयार करने को बल मिल सकेगा।' उन्होंने सार्क को भविष्य में दुनिया के इस हिस्से में शांति, विकास और स्थायित्व को प्रोत्साहित करने वाले उपकरण के रुप में देखा था। सार्क को ''सदस्य देशों के बीच संप्रभुत्ता बढ़ाने और शांति, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय के अलावा इसे दक्षिण एशियाई देशों की समृद्धि और कल्याण को प्रोत्साहन देने और यहॉ बसने वाले लोगों का जीवनस्तर सुधारने वाली रुपरेखा के तौर पर देखा गया था।''

सार्क के अस्तित्व में आने के ढाई दशक के दौरान क्षेत्रीय सहयोग के प्रतिरुप को 16वें शिखर सम्मेलनों और दर्जनों मंत्रीस्तरीय बैठको के साथ–साथ विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रही नागरिक संस्थाओं की विभिन्न गतिविधि के जरिए प्रोत्साहित किया गया (शर्मा 2010) भूटान में आयोजित 16वें शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के प्रसांगिक आह्वान का ध्यान रखने की जरुरत है। उन्होंने कहा था, 'दक्षिण एशिया के एक साथ आगे बढ़ने तक 21वीं सदी एशिया की सदी नहीं हो सकती। हमने क्षेत्रीय सहयोग के लिए संस्थान बना लिया, लेकिन उसे उर्वर बनाने के लिए हम उसे अभी तक पर्याप्त रुप से शक्तिशाली नहीं बना सके हैं।' (मनमोहन सिंह 2010)

सार्क की विफलताः बाह्य या आंतरिक

ढांचे के लिहाज से सार्क का पुर्नसंयोजन समय की मांग है। इसके बगैर किसी प्रगति के साथ–साथ दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग की चुनौतियों पर पार पाने की उम्मीद करना बेहद कठिन है। सार्क के चार्टर में विवादित द्विपक्षीय मुद्दों को सिरे से नकारने का सैद्धांतिक रुप से ध्यान रखा गया है और इस बात पर जोर दिया गया है कि सभी फैसले सर्वसम्मति से ही लिए जाएंगे। यह प्रमाणित है कि स्वंय की बंदिशों के कारण सार्क की संरचना में ही विफलता और बाधाएं अंतर्निहित है। अर्थात सार्क का ढांचा ही क्षेत्रीय सहयोग में अक्सर आड़े आता रहता है। उदाहरण के लिए यदि एक भी सदस्य देश की सरकार या मुखिया मजबूरी जताए तो शिखर सम्मेलन टालना पड़ता है।

एक संस्था के रुप में भी सार्क अपने गठन के बाद 33 वर्षों में विभिन्न मौकों पर मौन व्रतधारी ही बना रहा है। निश्चित रुप से सार्क की पहचान या दक्षिण एशिया की एकजुटता एक राजनीतिक मुखौटा बन कर रह गया है। सार्क का ढांचा ही इतना कमजोर हो चुका है कि यह नेताओं के बीच बातचीत का मंच बन कर रह गया है। एक शक्तिशाली क्षेत्रीय निकाय के रुप में उभरने से सार्क की विफलता के पीछे उसका संचालित स्वरुप है। देशों के बीच विवादों में झांकने की इसकी अक्षमता अक्सर इसे द्विपक्षीय विवादों और सदस्य देशों के निजी हितों की गिरवी बनाता है। सफलता की राह से सार्क के सामने जो बाधांए हैं उनमें से एक गंभीर समस्या संसाधन की कमी है। सदस्य देश संगठन को अपना अंशदान बढ़ाने में कोई रुचि नहीं दिखा रहे। इसके विपरीत हर सदस्य देश अपने घरेलू हितों के प्रति अत्यंत आग्रही है। सभी सदस्य देश सार्क से ज्यादा से ज्यादा लाभ लेना चाहते हैं और बदले में दूसरे सदस्य देशों के साथ कम से कम साझा करना चाहते हैं। क्षेत्रीय साझेदारी मददगार संस्था की जगह सार्क आज भी दक्षिण एशिया की एकता का मुखौटा होने का कलंक ढो रहा है। आम राय में दक्षिण एशिया को लाभ पहुँचाने वाले उपायों की जगह सार्क सहयोग के लिए सदस्य देशों के बीच निचले स्तर पर समझौते करने वाली संस्था है। हालांकि कागजों में इसकी सफलता की गाथांए लिखी गई है। अपनी दुर्दशा से सार्क बाहर आएगा या नहीं इसके बारे में बिट्रेन की एक आर्थिक पत्रिका ने अपने विचार व्यक्त किए है।

आलोचना में कहा गया हैं कि दक्षिण एशिया की क्षेत्रीय भावना को कमजोर करने वाले क्षेत्र के भीतर के राजनीतिक तनावों के कारण सार्क एक निष्क्रिय संस्था बन कर रह गई है। राजनीति संचालित द्विपक्षीय पहलों को संदेह और गलतफहमी ने ढंक रखा है। राजनीति और फूट डालने वाले मुद्दों से ग्रस्त राजनीतिक रुप से दुर्बल सरकार अनसुलझे विवादों का शिकार हो जाती हैं और भ्रम, संदेह और अविश्वास पर काबू पाने की उनकी अक्षमता सार्क की दक्षिण एशिया में नेतृत्व की भूमिका अदा करने और उम्मीदों पर खरा उतरने में अवरोध बन जाती है। शीतयुद्ध से प्रभावित खास तरह की राजनीतिक विचारधारा का प्रभाव दक्षिण एशिया में गड़बड़ी या अस्थिरता के रुप में पड़ा। लेकिन, उसी दौरान एक वैचारिक बंधन के अभाव के कारण दक्षिण एशिया के निवासियों को उदासीन और एक दूसरे से अलग–थलग रखा, जबकि गरीबी जैसी साझी बीमारी से ग्रस्त होने के कारण वे एक दूसरे की दुर्दशा को आसानी से समझ सकते थे। (इज्जादीन 2007)

सार्क के विस्तार के जरिए एक बड़े संघ, क्षेत्रीयता के सपने से देशों के बीच द्विपक्षीय अविश्वास के नकारात्मक प्रभावों को दरकिनार करने की उम्मीद की जाती है। लेकिन, अप्रैल 2007 में अफगानिस्तान का सार्क में शामिल होना पाकिस्तान को और असहज कर गया। इसी तरह क्रमशः चीन और ईरान को प्रेक्षक की हैसियत मिलना भारत और अमेरिका के लिए हार के जैसा माना गया। सार्क के छोटे देश चीन की सदस्यता को सार्क के भीतर भारत की ताकत को संतुलित करने के उपाय के रुप में मान रहे हैं। 2005 में आस्ट्रेलिया, चीन, यूरोपीय यूनियन, ईरान, जापान, दक्षिण कारिया, मरीशस, म्यांमार और अमेरिका को प्रेक्षक की हैसियत दी जा चुकी हैं। बाहरी ताकतों की सार्क में लगातार बढ़ती रुचि को दक्षिण एशिया के लिए इस तथ्य को समझने के एक सूचकांक के रुप में लिया जाना चाहिए कि जितना इसके सदस्य देशों की समझ से कही ज्यादा यह निकाय उपयोगी हैं। यहां मद्रास विश्वविद्यालय, चेन्नई में रक्षा एवं रणनीतिक अध्ययन विभाग के एक राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर गोपालजी मालवीय का उल्लेख करना प्रासंगिक रहेगा। सार्क की सदस्यता हासिल करने की कई देशों के प्रयास के परिपेक्ष्य में विफलता के कलंक के सबसे बड़े आलोचक है। (मालवीय 2010)

सार्क : भारत के लिए निराशाजनक भविष्य

सार्क की सफलता ढपोरशंखी दावों के बजाय क्षेत्र के देशों के स्थायी बदलाव पर निर्भर होने के परिपेक्ष्य में यह संगठन असल में अभिलाषाओं को पूरा करने में विफल रहा है। 33 साल की यात्रा के दौरान सार्क के खाते में मामूली सफलताएं ही आ सकी है। इस बात का उल्लेख भूटान में आयोजित 16वें शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी किया था। भारत के विदेश सचिव श्याम सरन ने भी ''स्वाग्राही राष्ट्रवाद के बढ़ने से विभाजन आघात'' को लेकर संदेह जताया था। इसके कारण सार्क की एकजुटता की दिशा में प्रगति धीमी रहीं। यदि बड़े पैमाने पर स्वगृहीत बाधाएं जारी रहीं तो सार्क को एक उपयोगी क्षेत्रीय संगठन बनने से रोकने के लिए और भी कई रुकावटें सामने आएंगी। (मसूद 2005)

सार्क के अन्य सदस्य भारत के प्रति सावधान

जाहिर तौर पर भारत क्षेत्र में अन्य देशों से बहुत आगे है। विशिष्ट और विशाल भौगोलिक आकार, परंपरागत और सांस्कृतिक संपर्क, जनसंख्या और आर्थिक क्षमता, राजनीतिक रसूख और रणनीतिक क्षमता में यह अपने क्षेत्र के बाकी देशों से कहीं आगे है। अपने तीव्र आर्थिक विकास में भारत की मदद की दरकार और क्षेत्रीय संगठन में उसके बड़ी भूमिका से पूर्णतः वाकिफ होने के बावजूद दक्षिण एशिया के छोटे देश भारत के साथ काम करने से कतराते है। उन्हें इस बात का डर है कि भारत पर किसी रुप में निर्भरता का अर्थ सार्क में भारत के दबदबे को स्वीकार करना होगा। या सहयोगी नीति के जरिए अंतर्निर्भरता भारत के साथ द्विपक्षीय विवादों का सम्मानजनक हल निकालने में उनकी सुविधाजनक स्थिति को चोट पहुंचाएगा। इसलिए संस्थागत सुरक्षा तंत्र के अभाव में सार्क के भीतर कई विवादों के समाधान की प्रक्रिया अटक गई। भारत भी समान रुप से अपने हितों के खिलाफ पड़ोसियों की संभावित एकजुटता को लेकर ऑखें चढाए रहता है। संघ की प्रगति का मतलब सार्क में भारत का दबदबा होना भांप कर इससे डरा पाकिस्तान गुप्त रुप से दक्षिण एशिया के मामलों में चीन को सामने लाने की चाल चल रहा है।

रणनीतिक रुप से भारत का अग्रणी होना और इसकी भौगोलिक स्थिति दक्षिण एशिया में उसके पड़ोसी मुल्कों के लिए लगातार चिंता का मुख्य कारण है। सार्क के हर देश के साथ भारत की सीमा या तो समुद्र से या फिर जमीन से लगती है, जबकि अन्य किसी भी देश की सीमाएं इस तरह से एक दूसरे से नहीं लगती। हालांकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा साझी है, लेकिन

ये दोनों देश भी सार्क के अन्य देशों के साथ भारतीय क्षेत्र के माध्यम से ही संपर्क साध सकते है। भूटान और बाग्लादेश की सीमाएं एक दूसरे से महज कुछ ही किलोमीटर पर स्थित हैं, फिर भी वे भौगोलिक रुप से एक दूसरे से जुदा हैं। इसी तरह नेपाल और भूटान की भौगोलिक स्थिति भी ऐसी है कि दोनों देश भारत पर निर्भर हैं और दोनों के विदेश व्यापार और पारगमन के लिहाज से भारत का नियंत्रण है। इस दृष्टि से इन छोटे देशों का द्विपक्षीय व्यापार, सीमा पार करना, ऊर्जा समझौते या अन्य आपसी गतिविधि भारतीय सहयोग के बगैर प्रतिबाधित हैं। इस सबके होते हुए भारत भी इन देशों के साथ क्षेत्रीय विवाद की दशा में असुरक्षित हैं।

सार्क का कमजोर व्यापार संपर्क

निकटस्थ देशों का समूह होने के बावजूद दक्षिण एशिया दुनिया में बिखराव का शिकार क्षेत्रों में से एक है। सार्क के महासचिव शील कांत शर्मा के मुताबिक ''दक्षिण एशिया के आठों देशों के बीच संपर्क का अभाव अंतर–क्षेत्रीय व्यापार की राह में सबसे बड़ी रुकावट है।'' (महासचिव 2010) असल में दक्षिण एशिया के देशों ने कई द्विपक्षीय निवेश समझौते क्षेत्र के बाहर देशों के साथ किए हैं। भारत के विविधता वाले व्यापार टोकरे के बावजूद सार्क के देशों के पास व्यापार साझीदार के रुप में क्षेत्र से बाहर की शक्तियॉ हासिल है। बाजार का आकार और मध्य में स्थित होने के कारण दक्षिण एशिया में होने वाले 80 फीसदी अंतर–क्षेत्रीय व्यापार में भारत की भागीदारी रहती है। सार्क के अन्य देशों के बीच आपसी व्यापार न्यून होता है।

भारत सार्क के सदस्य देशों के साथ आम तौर पर व्यापार संतुलन बनाए रखता है और व्यापार अधिशेष 23 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़ कर हाल तक 50 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुॅच गया। दक्षिण एशिया के करीब–करीब सभी देशों में घरेलू उद्योगों को कड़ी विदेशी प्रतिस्पर्द्धा से बचाए रखने और क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रतिबंधित रखने के लिए आयात प्रतिस्थापन और विनिमय नियंत्रण, उच्च शुल्क ढांचा और आयात नियंत्रण व्यवस्था समेत कठोर आर्थिक प्रबंधन का लंबे समय तक प्रचलन रहा। अत्यंत कम कौशल पूर्ण निर्यात और बड़े पैमाने पर अकुशल मजदूरों और संसाधन आधारित उत्पादों के अलावा दक्षिण एशिया में अंतर–क्षेत्रीय निर्यात में सामान्य खाद्य पदार्थों और कृषि उत्पादों का बोलबाला था। ऐसे उत्पादों के लिए मांग का अनुमान नहीं लगाया जा सकता था और यह घरेलू आपूर्ति स्थिति और दक्षिण एशिया के देशों की सरकारों की मनमानी नीतियों पर आश्रित था। सार्क के छोटे देशों को अक्सर यह डर सताता रहता था कि भारतीय समान से उनके बाजार सज जाने पर उनके घरेलू उद्योग बर्बाद हो जाएंगे। क्षेत्रीय व्यापार बढ़ाने के सार्क के प्रयासों को अक्सर अंतर–देशी खास तौर से भारत–पाकिस्तान के विवादों से चुनौती मिली। एसोचैम के अध्यक्ष अनिल के अग्रवाल ने राजनीतिक तनाव और सार्क देशों के बीच भारत को लेकर अविश्वास के कारण सार्क में कारोबारी प्रदर्शन को शून्य करार दिया। (एसोचैम 2006) अब दक्षिण एशिया में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बल देने के एक प्रयास के तहत भारत ने सार्क के अन्य देशों से आयात की अनुमति दी है। इसके परिणामस्वरुप पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान और बांग्लादेश से आयात में तीव्र वृद्धि हुई है।

क्षेत्र से भारत के सकल आयात का 31 प्रतिशत हिस्सा कब्जा कर श्रीलंका सबसे आगे है। इसके बाद पाकिस्तान 21 प्रतिशत नेपाल 20 प्रतिशत, बांग्लादेश 15 प्रतिशत और भूटान की 9 प्रतिशत हिस्सेदारी हैं। कुछ क्षेत्रीय देशों के बीच अयोग्य प्रतिस्पर्द्धा है क्योंकि दक्षिण एशिया के व्यापार टोकरे में ज्यादातार कच्चा माल और कपड़े, सिले सिलाए वस्त्र (निर्यात) पूंजीगत सामान और उच्च तकनीक उत्पाद (मुख्य आयात) से भरे हुए हैं। अंतर्क्षेत्रीय व्यापार के विस्तार पर ढांचागत दबाव के साथ उत्पादों की सापेक्षिक संकीर्ण श्रृंखला में कुल मिलाकर समरुप तुलनात्मक लाभ की पद्धति, व्यापार ढांचे में पूरकता की न्यूनता या उसका अभाव और उच्च लागत वाले और उच्च मूल्यवर्धित उत्पादों में तुलनात्मक लाभ के अभाव का भी असर हैं। बंदिशों वाली व्यापार नीति भी अंतर–क्षेत्रीय व्यापार का आकार छोटा रखने के लिए जिम्मेवार हैं। कुल मिलाकर अंतर क्षेत्रीय व्यापार का स्तर नीचे रहना व्यापार संरचना में समरुपता लाता है। जिसे वस्तु–पक्षपात के नाम से जाना जाता है। रियायती शुल्क और कम विकसित देशों को सकारात्मक माहौल उपलब्ध कराने जैसे उपायों के द्वारा व्यापार समझौतों में तेजी लाने की पहल की गई। उदारीकरण का इसी धीमे उपाय का निष्कर्ष साउथ एशिया प्रिफेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट (साफ्टा) हैं। बाद में जुलाई 2006 में साफ्टा सक्रिय हुआ। उम्मीद थी कि साफ्टा पूरी तरह से दक्षिण एशिया आर्थिक संघ के रुप में उभरेगा। यदि साफ्टा लागू होता है तो इससे भारत को सार्क देशों के साथ व्यापारिक रिश्ते को मजबूती प्रदान करने में मदद मिलेगी। विडंबना है कि अंतर–क्षेत्रीय व्यापार कछुए की चाल चल रहा है। 1980 में यह जहॉ 3.2 प्रतिशत था। वहीं 2008 में मामूली बढ़त के साथ महज 5. 5 प्रतिशत तक पहुंच सका। यह वृद्धि नाफ्टा में 58 प्रतिशत यूरोपीय यूनियन में 54 प्रतिशत और अशियान में करीब 27 प्रतिशत और कोमेसा में 22 प्रतिशत की तुलना में नगण्य है।

भारत को सम्मोहित करता आशियान इतिहास और भूगोल के जरिए दक्षिण पूर्व एशिया पर भारत की निगाह

इतिहास (सांस्कृतिक प्रभाव) में सदृश्यता और भूगोल (भौतिक गठन और आर्थिक आधार) भारत को दक्षिण–पूर्व एशिया को बेहतर तरीके से समझने के लिए किसी अन्य के मुकाबले वृहत्तर अवसर मुहैया कराता है। विशेष रुप से सांस्कृतिक समावेशन और कृषि कार्यविधि के लिहाज से भारत और दक्षिण–पूर्व एशिया का मानवीय भूगोल, इतिहास के भौगोलिक संबंध को प्रमाणित करते हैं। हालांकि भारत ने एशिया–प्रशांत क्षेत्र में गहरे ''भौगोलिक पदचिन्ह'' हासिल कर लिए हैं, फिर भी गुटनिरपेक्षता के सिद्धान्तों के प्रति गहरी प्रतिबद्धता ने इसे उपदेशक की भूमिका में और अंततः अलग–थलग स्थिति में ला खड़ा कर दिया। शीत युद्ध के परिपेक्ष्य में विशिष्ट खतरे के अनुमान के कारण भारत किसी भी क्षेत्रीय सुरक्षा समझौते से दूर ही रहा। साउथइस्ट एशियन नेशन्स (आसियान 1967) के गठन को लेकर उदासीनता और दक्षिण एशिया की राजनीति के प्रति गहरा लगाव रखने के कारण शीत युद्ध के दौरान भारत और दक्षिण–पूर्व एशिया के देशों के बीच खाई चौड़ी होती गई। शीतयुद्ध का उन्माद मंद पड़ने के साथ–साथ वैश्विकरण की नई अर्थव्यवस्था के जोर पकड़ते ही भारत ने दक्षिण–पूर्व एशिया के अपने पड़ोसियों के साथ संबंध सुधारने के लिए ऐतिहासिक संपर्कों और सांस्कृतिक संबंधों पर पड़ी गर्द झाड़ना शुरु कर दिया। भारत के आसियान के साथ फिर से संबंध बनाने में असली कामयाबी सहजीवी रीति और आपसी हितों का सम्मान करने की नीति अपनाने के साथ ही क्षेत्रीय सहयोग प्रयासों को अमल में लाने से मिली।

भारत के दक्षिण–पूर्व एशिया के साझे संपर्कों और चिंताओं पर गहरी नजर डालने से पूर्व नीति और अधिक व्यावहार्य लक्ष्य हो गई जिससे अन्य देशों को लंबे समय तक आसियान से अपेक्षाओं को पूरा करने में मदद मिल सकती थी। वे ऑफ बंगाल इनीशिएटिव फॉर मल्टीसेक्टोरल साईटिफिक एंड टेक्निकल कोऑपरेशन (बिम्सटेक) का उद्धदेश्य ''व्यापार संभावनाओं की तलाश'' और ''क्षेत्र

में संपर्क'' विकसित करना था। यह कदम ''पडोस विस्तार'' करने के विचार का वास्तविकीकरण था। मीकांग–गंगा कोऑपरेशन (एमजीसी) ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक संबंधों पर बल देने और ''आय और लाभ से प्रेरित आर्थिक एवं सामाजिक हित सुनिश्चित करने'' का एक और प्रयास था। क्षेत्र की संभावना के दोहन के एवज में किए जाने वाले प्रयास के रुप में देखा गया एमसीजी एक निष्ठापूर्ण चिंतन का दस्तावेज, ''सहजीवी पहल है।

भारत–पाकिस्तान व्यापारिक संभावना पूरकता पर आधारित

भारत और दक्षिण–पूर्व एशिया के बीच महत्वपूर्ण पूरकता आर्थिक सहयोग के परस्पर निर्भरता के सिद्धान्त पर आश्रित है। परस्पर आदान प्रदान के इस प्रकार को सर्वहितकारी चतुराई कहा जा सकता है। उप–क्षेत्रीय स्तर पर समरुप आर्थिक रणनीति के मौजूद रहने और सीमित पूरकता के कारण उपर्युक्त युक्ति चाहे आसियान हो या सार्क दोनों ही में अंतर–क्षेत्रीय व्यापार की सीमित संभावना के विपरीत है। यहां तक कि प्राथमिक उत्पादों में भी व्यापार संभावना को प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता, क्योंकि उस दशा विशेष फसल इसके घेरे में नही आती। इसका श्रेय औपनिवेशिक शासकों को जाता है जिन्होंने नई किस्म की कीमती नगदी फसलों की खेती शुरु कराई थी। भारत का निरुत्साही रुख और आसियान का पश्चिम के साझीदारों को तरजीह देने की विरोधाभासी स्थिति के अलावा समान उत्पादन के लिए प्रतियोगी व्यापार व्यवस्था व्यापार ढांचे की गहराई की तलहटी में है। यही भारत–दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के देशों की विपुल संभावना को महत्वहीन बना रहा है। मेंकांग–गंगा घाटी के देशों के लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंटस् (मुक्त व्यापार समझौते) और रीजनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एरियाज (क्षेत्रीय व्यापार निवेश क्षेत्र) के जरिए सहजीवी स्वरुप विकसित करने का यह उपयुक्त समय है। मुक्त व्यापार समझौता भारत की पूर्वाभिमुखी नीति का हिस्सा है जिसके तहत यह दक्षिण–पूर्व एशिया के देशों के साथ आर्थिक और रणनीतिक संबंध मजबूत करना चाहता है। व्यापार फायदे के अलावा भारत ने आसियान इंटीग्रेशन ध्वजवाहक परियोजनाओं में भागीदारी लेने में गहरी रुचि दिखाई है। इसका लक्ष्य कम विकसित सीएलएमवी देशों को एमजीसी के माध्यम से आसियान की मुख्यधारा से जोड़ना हैं। भारत–आसियान मुक्ट व्यापार समझौता, अक्टूबर 2003 में बाली में आयोजित दूसरे भारत–आसियान शिखर सम्मेलन की कार्यसूची में रखा गया और भारत एवं आशियान के बीच कम्प्रीहेंसिव इकॉनॉमिक कोऑपरेशन (समग्र आर्थिक सहयोग) पर समझौते की रुपरेखा के रुप में लिया गया। सीईसीए का उद्धदेश्य पक्षों के बीच अवरोधों को कम और आर्थिक संपर्कों को गहरा करना, लागत घटाना, अंतः क्षेत्रीय व्यापार एवं निवेश को तीव्र करना, आर्थिक क्षमता को बढ़ाना, पक्षों के कारोबार के लिए विपुल संभावनाओं के साथ बड़ा बाजार और विस्तृत अर्थव्यवस्था विकसित करना और पक्षों में पूंजी और प्रतिभा के प्रति आकर्षण बढ़ाना है।

भारत : सार्क और आशियान

भारत के विदेश सचिव श्याम सरण का स्पष्ट आश्वासन था, ''भारत एक अवसर है कोई खतरा नहीं।'' सार्क के मामले में भारत आर्थिक शक्ति, सैन्य बल और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव के लिहाज से सबसे अधिक ताकतवर देश है और इसीलिए यह प्रत्यक्ष या परोक्ष रुप से केंद्र में मौजूद है। स्पष्ट रुप से सार्क की सफलता पड़ोसी मुल्कों द्वारा भारत को स्वीकार करने पर निर्भर है। इसका कारण यह है कि यह सार्क का इंजन और आर्थिक संचालन शक्ति है। अतः इस लिहाज से भारत के लिए भी विश्वासपूर्ण और भरोसे के माहौल में पड़ोसियों को अपने साथ लेकर चलने की जिम्मेवारी बनती हैं। दुर्भाग्यवश सन्निकट पड़ोसी भारत को एक साथ मुक्तिदाता और समस्या का हिस्सा के रुप में देखते है। अपने नागरिकों का ध्यान असली समस्या से हटाने और अपनी नाकामी छिपाने के लिए ये पड़ोसी अक्सर आंतरिक अस्थिरता और हिंसा के लिए भारत पर जिम्मेवारी थोपते रहते हैं। दक्षिण एशिया के पड़ोसियों के बीच विश्वास, एकजुटता, शांति संरक्षणवाद और स्थायित्व की कमी ने उन्हें भारत के प्रति नकारात्मक सोच और गलतफहमी पालने के साथ–साथ गर्व और पूर्वाग्रह रखने का आदी बना दिया है। चेष्टा और उदारता दिखाने के बावजूद भारत भी समान रुप से अपने छोटे पड़ोसियों के प्रति संदेह बाधा से ग्रसत है।

भारत क्षेत्र के देशों के फायदे के लिए सार्क में एक असममित और गैर पारस्परिक ढंग से अपनी जवाबदेही को पूरा करने के लिए कृतसंकल्प है। सार्क की सफलता या विफलता के लिए भारत अन्य के मुकाबले असमानुपातिक जवाबदेही रखता है। (राजन, एन.डी.) दक्षिण एशिया में भारत बहुत कम रुचि रखता है और इसीलिए सार्क एक महत्वपूर्ण विकल्प तो है, लेकिन एकमात्र विकल्प नहीं है। अतः एक क्षेत्रीय नेतृत्व के रुप में भारत की संभावना सार्क को आसियान जैसे संगठन की तुलना में अनोखा अवसर मुहैया कराता है। भारत के साथ दक्षिण–पूर्व एशिया के साथ दो हजार साल पुराने संबंध में कभी भी शोषण वाला रवैया नजर नहीं आता। आवरण शांतिपूर्ण और रुख सहयोगात्मक नजर आता है। दोनों के संबंध में कहीं भी राजनीतिक विजय और वाणिज्यिक संपर्क को घालमेल नहीं दिखता। रिश्ते को आर्थिक दोहन के रुप में कभी भी नहीं पहचाना गया। इसकी जगह पूर्वी पड़ोसियों के साथ भारत का दोस्ताना रिश्ता इतिहास के जरिए बराबरी पर पला बढ़ा। भारतीय राष्ट्रीय नैतिकता और चरित्र ने दक्षिण–पूर्व एशिया को भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन की भावना ग्रहण करने के लिए प्रेरित किया। इसके साथ ही दक्षिण–पूर्व एशिया के नव स्वतंत्र राष्ट्रों को उपनिवेश काल के बाद उभरी ताकत शून्यता के परिपेक्ष्य में सुरक्षा चिंता को लेकर भारत में भरोसा करना सिखाया। एशिया प्रशांत क्षेत्र में एकता और सहयोग को लेकर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पं. जवाहर लाल नेहरु का मसीही नजरिया इस प्रकार था,''हमारी कई समस्याएं खास कर प्रशांत और एशिया के दक्षिण–पूर्वी क्षेत्र में साझी है। हमें एक–दूसरे का सहयोग करना चाहिए और समाधान निकालना चाहिए।'' अंतर–देशीय, अंतर्देशीय और क्षेत्रीय विवादों से दूरी बना कर चलने वाला सार्क एक उदासीन क्षेत्रीय निकाय है। सार्क के अन्य सदस्य देशों के साथ भारत की असहजता भारत के लिए आसियान के साथ साझेदारी को तीव्र गति से आगे ले जाने में प्रोत्साहक का काम कर रहा है। इसके अलावा पूर्वी एशियाई समुदाय के साथ भारत की एकजुटता उसे एशिया प्रशांत बहुउद्देश्यवाद के परिप्रेक्ष्य में एक व्यापक सक्रियता आधारित रुख अपनाने का अवसर मुहैया कराता है। इसके अलावा उसे एशिया में शक्ति संतुलन के लिहाज से एक ताकत के रुप में उभरने और दक्षिण एशिया में चीन की उभर रही चुनौती की बराबरी का अवसर प्रदान करता है। यह महत्वपूर्ण है कि पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन में शामिल होने के बाद से भारत भी पूर्व एशियाई समुदाय का अभिन्न हिस्सा माना जाता है। भारत के लिए समर्थन का मुख्य कारण उसकी आर्थिक और रणनीतिक शक्ति को मिली मंजूरी है। सहयोग में और तीव्रता लाने की अभिरुची के साथ भारत–पाकिस्तान संबंध केंद्रीय मंच की तरफ बढ़ जाता है। और सहयोग कसे लिए सबसे ज्यादा प्रेरक है। आर्थिक हितों का समन्वय।

6–7 फरवरी 2005 को ढाका में आयोजित होने वाले 13वें सार्क

शिखर सम्मेलन के बारे में यह उल्लेख किया गया है। यह सम्मेलन भारत के इसमें हिस्सा नहीं लेने के फैसले के कारण नहीं हो पाया। भारत ने नेपाल में तत्कालीन नेपाल नरेश ज्ञानेंद्र द्वारा शेर बहादुर देउबा की साझा सरकार को बर्खास्त करने पर चिंता जताते हुए सम्मेलन में हिस्सा लेने से मना कर दिया था। भारत के इस फेसले से बड़े पैमाने पर अविश्वास और निराशा पैदा हुई। ऐसी समस्या के समाधान होने तक सार्क शिखर सम्मेलनों में हिस्सा नहीं लेने की भारत की घोषणा को पड़ोसियों के घरेलू मामले में दखल देने के जैसा कदम माना गया। इस कदम से भारत की संभावना पर आज तक संदेह की काली छाया पड़ी हुई है।

सन्दर्भ

1. वी0सी0 उत्प्रेती : 'सार्क डाइनामिक्स ऑफ रीजनल को–ऑपरेशन इन साऊथ एशिया, अंक 6, पृ0 285
2. जिलुर आर0, खान : 'सार्क एण्ड दि सुपरपावर, यूनिवर्सिटी प्रेस लिमिटेड, ढाका, 1998, पृ0 60
3. स्मृति एस0 पटनायक : 'मेकिग सेंस ऑफ रिजनल को–ऑपरेशन : सार्क ऐट ट्वेटी', स्ट्रैटजिक एनालिसिस, नई दिल्ली, खण्ड 30, संख्या 1, 2014
4. Ahmed, Zahid Shahab and Bhatnagar, Stuti, 2008 "Interstate Conflcits and Regionalism in South Asia: Prospects and Challenges", Perceptions, Spring-Summer 2008, pp. 1-19,
5. India and AS
6. EAN keen to ramp up Bilateral Trade, Straits Times, 3 March 2011, Financial Express, 2009, Poor connectivity hampers SAARC trade, 22 November 2009. IPCS Panel discussion, 2007.
7. SAARC: Towards Greater connectivity, centre for SAARC Studies, Andhra University, Visakhaptnam, 2-3 March 2010.
8. Manmohan Singh, 2010 SAARC is glass half empty, region needs empowerment: Address at the 16th SAARC Summit, 28 April 2010, at.
9. Asima, Challenges for SAARC, Pakistan Times, 17 February. Program on Peace Studies and Conflict Resolution, 2010-2011.
10. Two-Day Regional Workshop: Restructuring of SAARC, organized by the Program on Peace Studies and Conflict Resolution, Department of International Relations. University of Karachi University of Karachi, 2010.